सण्डीला मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना ने पकड़ी तेजी

- ***रु 2000 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश अनुमानित, 10,000 नवीन रोजगार का सृजन***
- ***रु 400 करोड़ की लागत से 2 वर्ष में तैयार होने की सम्भावना***

लखनऊ, 08 अक्तूबर 2013:

उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा वृहद् औद्योगिक अवस्थापना विकास हेतु प्रयासों के तहत आज **प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी), डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ने जनपद हरदोई में सण्डीला औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रीन–फील्ड मेगा लेदर क्लस्टर के परियोजना स्थल का निरीक्षण किया।** उनके साथ **प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी), मनोज सिंह** एवं अन्य अधिकारियों ने भी औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। **सण्डीला मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना के क्रियान्वयन हेतु यूपीएसआईडीसी नोडल संस्था है। लगभग रु 2000 करोड़ के अनुमानित पूंजी निवेश से मेगा लेदर क्लस्टर में 10,000 नवीन रोजगार के अवसरों का सृजन अपेक्षित है।**

प्रमुख सचिव, आईआईडीडी, डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ने कहा–*"क्योंकि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग की जड़ें पारम्परिक रूप से मज़बूत हैं अतः राज्य इस सेक्टर में तुलनात्मक रूप से लाभ की स्थिति में है। विश्व–स्तरीय सुविधाओं एवं नवीनतम तकनीक से सुसज्जित सण्डीला मेगा लेदर क्लस्टर के बन जाने से चमड़ा उद्यमियों को इस अग्रिम लाभ में गुणात्मक वृद्धि करने का अवसर मिलेगा।"*

यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों को परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए **डॉ सूर्य प्रताप सिंह ने कहा**–*"मेगा लेदर क्लस्टर के त्वरित विकास हेतु आने वाली सभी बाधाओं का त्वरित निस्तारण करना होगा, क्योंकि इस परियोजना से न केवल विद्यमान चमड़ा प्रसंस्करण इकाइयों को लाभ होगा अपितु इससे क्षेत्र की जनता को नये रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे।"*

उन्होंने कहा कि यदि सभी औपचारिकताएं समय से पूर्ण हो गईं तो मेगा लेदर क्लस्टर वर्ष 2015 के मध्य तक तैयार हो जाएगा।

परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति के विषय में **प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी, मनोज सिंह ने बताया**– *"सण्डीला मेगा लेदर क्लस्टर के लिए भूमि का आवंटन, इसके विकास हेतु गठित विशेष परियोजना साधन (एसपीवी–स्पेशियल पर्पज़ व्हेकिल) को किया जा चुका है तथा एसपीवी ने भारत सरकार से पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर दिया है, जो शीघ्र ही अपेक्षित है।"*

प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी ने बताया *कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने केन्द्रीय अपशिष्ट शोधक संयत्र हेतु 80 एकड़ भूमि की अतिरिक्त आवश्यकता बताई है। जिसमें से 20 एकड़ भूमि यूपीएसआईडीसी परियोजना के प्रथम चरण में देने के लिए सहमत है।*

सण्डीला मेगा लेदर क्लस्टर को **रु 400 करोड़ की अनुमानित लागत** से एसपीवी के माध्यम से **162 एकड़ भूमि** पर विकसित किया जाएगा। *लेदर क्लस्टर डेवलवमेंट प्रा लि.* नामक एसपीवी का पंजीकरण हो चुका है। भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा लेदर क्लस्टर की स्थापना हेतु मंजूरी मिल चुकी है तथा भारत सरकार ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को भी सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित कर दिया है। जैसे ही भारत सरकार से पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त होगी, एसपीवी द्वारा मेगा लेदर क्लस्टर का विकास शुरू कर दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अपनी लेदर क्लस्टर स्कीम के तहत इस परियोजना के विकास हेतु रु 125 करोड़ की आर्थिक सहायता भी दी जानी है।

योजनानुसार मेगा लेदर क्लस्टर में 50 प्रतिशत् भूमि लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को दी जाएगी और उनके लिए आधुनिक सुविधाओं एवं तकनीक से सुसज्जित अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके अलावा अपशिष्ट शोधक संयत्र, वर्षा जल संचयन, वेयरहाउस, कच्चे माल के बैंक, प्रदर्शन केन्द्र, डिज़ाइन केन्द्र, मानव संसाधन विकास आदि के प्राविधान भी इस लेदर क्लस्टर में प्रस्तावित हैं। ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने हरदोई और कानपुर जनपद में भारत सरकार की स्कीम के अन्तर्गत दो ग्रीन–फील्ड मेगा लेदर क्लस्टरों के विकास की योजना प्रस्तावित की है।

———————